RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : बुधवार 13 सितंबर 2023 वर्ष 05 अंक 140 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) माहिम से विधायक सदा सरवनकर ने कहा उद्धव ठाकरे...

संजय राउत ने मनोहर जोशी के घर पर हमला करने के लिए उकसाया था

माहिम : शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के विधायक सदा सरवनकर ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने पहले उन्हें मुंबई के शिवाजी पार्क इलाके में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के आवास पर हमला करने के लिए उकसाया था। घटना के बारे में बताते हुए सदा सरवनकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने उन्हें अपने आवास पर बुलाया था और कहा था कि 2009 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सरवनकर को टिकट नहीं मिलेगा क्योंकि मनोहर जोशी ने उनकी उम्मीदवारी का विरोध किया था। इसलिए ठाकरे ने उन्हें जोशी के घर जाकर हमला करने का निर्देश दिया था ।

ठाकरे के आदेश के बाद, सरवणकर 15-20 पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जोशी के आवास के लिए रवाना हुए। हालाँकि, रास्ते में उन्हें संजय राउत का फोन आया और उनसे उनकी योजनाओं के बारे में पूछा गया। सरवणकर ने दावा किया कि राउत को जोशी के आवास पर हमले की योजना के बारे में पहले से ही पता था। इसके बाद राउत ने उन्हें पास के पेट्रोल पंप से पेट्रोल लाने और उनके आवास को जलाने का निर्देश दिया। जब सरवणकर मनोहर जोशी के आवास पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां कुछ शिवसेना कार्यकर्ता और मीडियाकर्मी पहले से ही मौजूद थे। हमले के बाद सरवणकर को उद्धव ठाकरे के करीबी मिलिंद नार्वेकर का फोन आया और उन्होंने उन्हें हमले के लिए बधाई दी और अगले दिन सुबह 11 बजे उन्हें उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री पर बुलाया। सरवणकर ने दावा किया कि नार्वेकर ने विधानसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी की पुष्टि भी कर दी है। अगले दिन, मातोश्री में, उद्धव ठाकरे ने कथित तौर पर मनोहर जोशी के घर पर सदा सर्वंकर के हमले की कवरेज से नाराज होकर उन पर अखबार के कुछ पन्ने फेंक दिए, और उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया। सरवणकर ने दावा किया कि इस घटना के दौरान संजय राउत भी मातोश्री में मौजूद थे। सदा सर्वंकर ने कहा कि मनोहर जोशी ने इस पूरी घटना की पुलिस से शिकायत नहीं की. उन्होंने कहा कि मनोहर जोशी उनके 'गुरु' (शिक्षक) की तरह हैं और उन्होंने उनके अधीन काम किया है। सरवनकर ने दावा किया कि उन्हें उद्धव ठाकरे और राउत ने उकसाया था और उनके गुरु के घर पर हमला करवाया था।

एनसीपी नेता नवाब मलिक को राहत...

मानहानि मामले में कोर्ट ने खारिज किया गैर जमानती वारंट

महाराष्ट्र : एनसीपी नेता नवाब मलिक को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल मानहानि मामले में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मंगलवार को नवाब मलिक के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट खारिज कर दिया है। यह गैर जमानती वारंट महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि के एक मामले में जारी किया गया था। जिसे भाजपा कार्यकर्ता मोहित भारतीय ने साल 2021 में नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज कराया था।

कोर्ट में पेश हुए नवाब

मलिक को खारिज हुआ गैर जमानती वारंट

मझगांव कोर्ट के एडिश्नल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एसबी काले ने बीते हफ्ते नवाब मलिक के खिलाफ यह गैर जमानती वारंट जारी किया था। दरअसल मानहानि मामले की सुनवाई पर नवाब मलिक बीते महीने कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, जिस पर कोर्ट ने एनसीपी नेता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। अब मंगलवार को नवाब मलिक के कोर्ट में पेश होने पर उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को खारिज कर दिया गया है।

क्या है मामला

कोर्ट ने सबूतों की रिकॉर्डिंग के लिए 25 अक्तूबर तक मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। बता दें कि अक्तूबर 2021 को मोहित भारतीय ने नवाब मलिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि नवाब मलिक ने क्रूज ड्रग्स जब्ती मामले में उनके और उनके रिश्तेदार के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाए। बता दें कि क्रूज ड्रग्स जब्ती मामले में ही बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान गिरफ्तार हुआ था।

दाऊद इब्राहिम से जुड़े मामले में गिरफ्तार हुए थे नवाब मलिक...

मोहित भारतीय ने शिकायत में बताया कि नवाब मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानबूझकर उसे और उसके बहनोई ऋषभ सचदेव को बदनाम करने की कोशिश की और अपने दावों के पक्ष में कोई सबूत भी नहीं दिया। मोहित भारतीय ने नवाब मलिक के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 के तहत मामला दर्ज कराया था। ईडी ने फरवरी 2022 को भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। फिलहाल मलिक चिकित्सीय आधार पर अंतरिम जमानत पर बाहर हैं।

मुख्यमंत्री शिंदे का दावा, पिछले डेढ़ साल में 3 लाख युवाओं को दिया रोजगार...

महाराष्ट्र : हाल ही में आई खबर के मुताबिक, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि पिछले डेढ़ साल में कौशल विकास विभाग के जरिये तीन लाख अभ्यर्थियों को रोजगार मिला है। आगे उन्होंने कहा कि भारत को एक युवा देश के रूप में जाना जाता है। सरकार युवाओं को कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करने का प्रयास कर रही है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिंदे

आपको बता दें कि कौशल, रोजगार, उद्यमिता एवं नवाचार विभाग के अंतर्गत 418 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विद्वानों की कक्षाओं के लिए ऑनलाइन उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। उस समय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोल रहे थे। इस ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान कौशल, रोजगार विभाग मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा, विधायक प्रकाश सुर्वे, अतिरिक्त मुख्य सचिव आशीष कुमार सिंह, कौशल विकास आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन सहित 418 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं विद्यार्थी ऑनलाइन उपस्थित थे। इस ऑनलाइन प्रोग्राम के दौरान बात करते हुए मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि आज चालीस हजार छात्र ऑनलाइन मौजूद हैं, मैं उन सभी को बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि छात्र खुद को विकसित करने के लिए नए खोले गए 75 वर्चुअल क्लासरूम और आज लॉन्च किए गए ट्यूटोरियल का लाभ उठाएंगे। आगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य हमेशा देश के ग्रोथ इंजन के रूप में काम कर रहा है। विदेशी निवेश और बुनियादी ढांचे में भी महाराष्ट्र पहले स्थान पर है।

डेढ़ साल में तीन लाख युवाओं को रोजगार

रोजगार के बारे में बात करते हुए आगे मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया है और देश में कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। इसी तर्ज पर कौशल विकास विभाग के माध्यम से प्रदेश में विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा के नेतृत्व में पिछले डेढ़ साल में तीन लाख युवाओं को रोजगार मिला है और भविष्य में कौशल हासिल करने वाले युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे। आगे मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि यह गर्व की बात है कि उद्यमिता के लिए आवश्यक नवीन प्रौद्योगिकियों को ध्यान में रखते हुए आईटीआई में विभिन्न 900 पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं।

संपादकीय / लेख

जनधन योजना ने किया कमाल

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

हाल में विश्व बैंक की इस रिपोर्ट ने सबका ध्यान खींचा कि भारत ने जनधन बैंक खातों, आधार और मोबाइल फोन के उपयोग से वित्तीय समावेशन दर को 80 प्रतिशत तक प्राप्त करने में केवल छह साल का समय लिया, जिसके लिए इस तरह के डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआइ के बिना 47 साल लग सकते थे। जिस देश में दिल्ली से एक रुपया चलता था तो गांव तक उसमें से 15 पैसे ही पहुंचते थे, उस देश में आज 100 के 100 पैसे पूरे मिल रहे हैं और वह भी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में, तो इसका श्रेय मोदी सरकार की वित्तीय समावेशन नीति को जाता है। देश के वित्तीय समावेशन की दिशा में 16 अगस्त, 2023 की तिथि किसी मील के पत्थर से कम नहीं है। इस दिन देश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले बैंक खातों की संख्या 50 करोड़ के रिकार्ड आंकड़े को पार कर गई। इन बैंक खातों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें से 56 प्रतिशत बैंक खाते महिलाओं के हैं और 67 प्रतिशत खाते ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्रों में खुले हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में वित्तीय समावेशन का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है? मोदी सरकार ने देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 28 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ऐसे परिवार को जीरो बैंक बैलेंस खाता उपलब्ध कराना था, जो बैंकिंग सेवा से नहीं जुड़े थे। इसके तहत हर परिवार के दो सदस्य जनधन खाता खोल सकते हैं।

जनधन खाते में पैसे जमा करने एवं निकालने पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। इन खातों में बिना किसी शुल्क के फंड ट्रांसफर और मोबाइल बैंकिंग सुविधा मिलती है। इन बैंक खातों में न्यूनतम राशि रखने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मुफ्त रुपे डेबिट कार्ड के अलावा 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट, दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। जनधन योजना के तहत खुले बैंक खातों का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि केंद्र सरकार को धन के रिसाव को रोकने में मदद मिली। इसके लिए सरकार ने जनधन-आधार-मोबाइल के गठजोड़ से देश में बिचौलिया मुक्त धन हस्तांतरण का नेटवर्क स्थापित किया। इससे हर स्तर पर मौजूद बिचौलियों द्वारा किया जाने वाला फजीर्वाड़ा रुका और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लक्षित वर्गों तक पहुंचने लगा।

आज जनधन बैंक खातों का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं की सब्सिडी, छात्रवृत्ति, पेंशन, आपदा सहायता जैसी तमाम योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने में किया जा रहा है। उदाहरण के लिए सरकार ने कोविड महामारी के दौरान जनधन खातों का इस्तेमाल किया और ग्रामीण परिवारों के खातों में तत्काल प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से धन भेजा। मात्र दस दिनों के भीतर 20 करोड़ से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में राशि भेजी गई। जिस देश में 'आपदा में अवसर' तलाशने वालों की कमी न हो, वहां यह एक बड़ी उपलब्धि है। वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार ने विभिन्न योजनाओं के 7.16 लाख करोड़ रुपये लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए, जो वित्त वर्ष 2013-14 में हस्तांतरित राशि (7,367 करोड़ रुपये) की तुलना में 100 गुना ज्यादा है। आज 53 केंद्रीय मंत्रालयों की 320 योजनाओं के लाभ डीबीटी के तहत सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जा रहे हैं। विश्व बैंक अध्यक्ष अजय बंगा ने डीबीटी की प्रशंसा करते हुए कहा था कि भारत सरकार का सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय है। उनके अनुसार डिजिटलीकरण सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क को मजबूत बनाता है। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी डीबीटी को गरीबी उन्मूलन का कारगर हथियार बताया है।

+91 99877 75650
editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

इस साल अगस्त तक मराठवाड़ा में 685 किसानों ने की आत्महत्या...

कृषि मंत्री के जिले में सबसे ज्यादा

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में किसानों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। खराब फसल, कर्ज चुकाने का दबाव और खराब माली हालत के चलते यहां साल 2023 में ही 685 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यह आंकड़ा 31 अगस्त तक का ही है, जिससे अधिकारियों और सरकार की चिंता बढ़ गई है। एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक, मौतों का सबसे ज्यादा आंकड़ा बीड जिले से है, जहां अब तक 186 किसान मौत को गले लगा चुके हैं। बीड महाराष्ट्र के मौजूदा कृषि मंत्री धनंजय मुंडे का गृह जिला है। मुंडे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अजित पवार गुट का हिस्सा हैं, जिसने हाल ही में शरद पवार के नेतृत्व को ठुकराते हुए सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होने का फैसला किया था। मुंडे को इसके दो हफ्ते बाद ही शिंदे सरकार में कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल गई थी। बता दें कि मध्य महाराष्ट्र का इस शुष्क क्षेत्र में आठ जिले- औरंगाबाद, जालना, बीड, परभनी, नांदेड, उस्मानाबाद, हिंगोली और लातूर हैं। यहां के डिवीजनल कमिश्नर के दफ्तर की रिपोर्ट के मुताबिक, एक जनवरी 2023 से 31 अगस्त 2023 के बीच मराठवाड़ा में 685 किसानों ने आत्महत्या कर ली। इनमें से 294 ने अपनी जान मानसून के महीनों यानी जून से अगस्त के बीच दे दी।

मराठवाड़ा का सूखा किसानों के लिए बड़ी समस्या

महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र इस साल भी बारिश की कमी से जूझ रहा है। यहां इस मानसून सीजन में 20.7 फीसदी तक कम बारिश हुई है। क्षेत्र में 11 सितंबर तक 455.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि मानसून में होने वाली औसत 574.4 मिमी बारिश से काफी कम है। मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा किसानों ने बीड में जान दी। इसके अलावा 2023 में अब तक उस्मानाबाद में 113 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। तीसरा नंबर नांदेड का है, जहां 110 किसानों ने जान दी है। औरंगाबाद में 95, परभनी में 58, लातूर में 51, जालना में 50 और हिंगोली में 22 किसान आत्महत्या कर चुके हैं।

आभूषण लूटने वाले दो लुटेरे गिरफ्तार...

वसई : पेल्हार पुलिस स्टेशन ने 24 घन्टे के अंदर जबरन आभूषण लूटने वाले दो लुटेरे को पकड़ने में सफल पाई है। इनके पास से 1 लाख से अधिक का माल जप्त करते हुए 2 अपराधों को सुलझाया है। यह कार्रवाई डीसीपी (परिमंडल 3) सुहास बावचे व एसीपी रामचंद्र देशमुख के मार्गदर्शन में पेल्हार थाने के सीनियर पी.आई.वसंत लब्दे, पीआई (क्राइम) विजय पाटील,पीआई (प्रशासन) शिवानंद देवकर व जांच अधिकारी पोउपनि तुकाराम भोपाले के नेतृत्व में अपराध जांच दल की टीम ने की है।

नालासोपारा पुलिस ने 3 चोरों को पकड़ा आठ अपराधों का किया पर्दाफाश...

नालासोपारा : नालासोपारा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके चोरी का सामान जब्त करके 8 अपराधों का पदार्फाश किया है। यह सफलता डीसीपी (परिमंडल 3) सुहास बावचे व एसीपी राजेंद्र मोकाशी के मार्गदर्शन में नालासोपारा पुलिस स्टेशन के सीनियर पी.आई.विजयसिंह बागल व पीआई (क्राइम) सचिन कोतमिरे के नेतृत्व में सपोनि.पंडीत मस्के की टीम ने दिलाई है।

नालासोपारा पुलिस स्टेशन में शिकायतकर्ता रफीकुल रझबअली गाझी (34) ने शिकायत दर्ज करवाया था की उनके चोरी हुई है। शिकायत के बाद वरिष्ठों द्वारा दिए गए निर्देश के बाद अपराध जांच शाखा की टीम के अधिकारी और कर्मचारी ने अज्ञात आरोपी के संबंध में कोई जानकारी न मिलने पर प्राप्त साक्ष्यों एवं तकनीकी जानकारी के आधार पर अपराध की जांच करते हुए आरोपी जुनेद अब्दुलकैस खान (28) व मोहम्मद यासीन पप्पु शेख (26) को गिरफ्तार कर लिया। जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने पहले भी नालासोपारा थाना (दर्ज गु.र.क्र. 125/2023 कलम 379,34) क्षेत्र में ऐसा ही चोरी की घटना किया था। वहीं आरोपियों के पास से चोरी का सामान बरामद कर लिया है।

म्हाडा के गले की हड्डी बन गए एक ही उपनाम के १९ विजेता

मुंबई : म्हाडा लॉटरी में फर्जी जानकारी देकर घर हथियाने वाले ७७ लोगों की जांच जारी है। यह मामला अभी शांत नहीं हुआ कि म्हाडा की लॉटरी में स्वतंत्रता सेनानी की श्रेणी में ४९ घरों में से एक ही उपनाम के १९ विजेता म्हाडा के गले की हड्डी बन गए हैं, जिनको म्हाडा ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। म्हाडा की लॉटरी पर लगी साढ़ेसाती दूर होने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में म्हाडा के महंगे घर के चलते ३९८ विजेताओं को लोन नहीं मिल पाने के चलते अपने घर म्हाडा को सरेंडर कर दिए, इतना ही नहीं सरेंडर करनेवालों की संख्या और बढ़ेगी।

गौरतलब है कि मुंबई में अपने सपनों के घर के लिए लोगों ने म्हाडा की लॉटरी में तरह-तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं। ४,०८२ घरों की लॉटरी में स्वतंत्रता सेनानी के लिए विशेष

आरक्षण दिया गया है। इस श्रेणी में स्वतंत्रता सेनानी या उसके परिवार के लोग एक ही बार लाभ ले सकते हैं। म्हाडा की इस लॉटरी के कोड क्रमांक ४१२ (प्रधान मंत्री आवास योजना), ४१५, ४१६ (पहाड़ी गोरेगांव अल्प श्रेणी) में एक ही उपनाम के १९ लोगों को लॉटरी लगी है, साथ ही सभी विजेताओं ने स्वीकृति पत्र भी प्रस्तुत किए हैं। म्हाडा ने इन पर शंका जाहिर करते हुए नोटिस जारी की है। बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी की श्रेणी में एक ही बार उसके परिवारजन लाभ ले सकते हैं।

वसई- विरार की सड़कों पर राहगीरों का चलना हुआ मुश्किल

वसई : विरार में अवैध फेरीवाले पर मनया की कार्रवाई नहीं होने से सड़कों और फुटपाथ पर फेरीवालों का कब्जा बढ़ता जा रहा है,जिसकी वजह से लोगों का चलना मुश्किल हो गया है,यहां आए दिन ट्रेफिक जाम की समस्या से लोग काफी परेशान हो रहे हैं, एक सर्वे के अनुसार बसई- विरार के हर गली मोहल्ला और सड़कों पर तालाबंदी से पहले लगभग डेढ़ लाख फेरीवाले थे, जो बढ़कर आज तीन लाख के करीब पहुंच चुके हैं, कुछ ही समय में दुगुना फेरीवालों की सांख्य बढ़ी है अलग- अलग महानगर पालिका क्षेत्र के फेरीवाले आ कर वसई -विरार क्षेत्र धंधा कर रहे हैं। फेरीवाले समस्या पर पिछले दिनों विधायक हितेंद्र ठाकुर ने मनपा अभिकारियों पर फेरीवालों से हप्ता कूलने का आरोप लगाया था, ठाकुर ने कहा था कि मनपा के अधिकारी हर फेरीवालों से पैसा जमा कर रहे हैं। इसकी वजह से सड़कों पर चार पहिया वाहन क्या दो पहिया वाहन चलन मुश्किल ' हो गया है। विधायक की फटकार के बाद भी कोई असर नहीं हुआ।

चूहों का बंदोबस्त करने के लिए मनपा ने तैयार किया प्लान 'डी'

मुंबई : लेप्टो के कारक चूहों का बंदोबस्त करने के लिए मनपा ने प्लान 'डी' तैयार किया है। इस प्लान से बीमारी फैलानेवाले चूहों की आबादी न केवल कंट्रोल होगी, बल्कि इनकी घरों में एंट्री भी रुकेगी। इतना ही नहीं चूहों के आश्रय को खत्म करने के लिए घर के आस-पास कोई भी संसाधन नहीं रखा जाएगा। इसके लिए कीटनाशक विभाग द्वारा व्यापक जनजागरूकता पैदा की जाएगी।

मुंबई में भले ही पूरे अगस्त महीने में बारिश का ब्रेक लग गया, लेकिन मानसूनी बीमारियों ने जोर पकड़ लिया है। इसमें मलेरिया, डेंगू, लेप्टो स्वाइन फ्लू, गैस्ट्रो, पीलिया और चिकनगुनिया जैसी मौसमी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं इसलिए मनपा के स्वास्थ्य और कीटनाशक नियंत्रण विभाग मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए २४ घंटे काम कर रहे हैं। मनपा के प्रमुख अस्पतालों के साथ-साथ उपनगरीय अस्पतालों में लगभग साढ़े तीन हजार बेड तैयार रखे गए हैं। इसी क्रम में कीटनाशक नियंत्रण विभाग ने लेप्टो के प्रसार के लिए जिम्मेदार चूहों को निर्यंत्रित करने के लिए ४डी विधि अपनाने का निर्णय लिया है।

लेप्टो प्रसार का कारण बननेवाले चूहों को खत्म करने के अभियान के तहत जनवरी से अब तक चार लाख चूहों का सफाया किया जा चुका है। मानसून की पृष्ठभूमि में चूहों के प्रकोप वाले स्थानों पर रात के समय जहरीली गोलियों को रखकर चूहा नाशक अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही नागरिकों की शिकायत के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। चूहों की प्रजनन दर, उसके कारण बीमारी के संभावित प्रसार और चूहों से होनेवाले विनाश पर अंकुश लगाने के लिए मूषक नियंत्रण उपक्रम चलाया जा रहा है। एक चूहे को मारने में २० से २५ रुपए खर्च हो रहे हैं।

चूहों को घर में घुसने से रोकने के लिए दरवाजे की दहलीज को ऊंचा करना, चूहों को छिपने का अवसर प्रदान करनेवाली वस्तुएं न रखें, चूहे को भोजन देना बंद कर दें, चूहे को पकड़ने के लिए पिंजरा रखें और घर में प्रवेश करने से रोकने का आखिरी विकल्प चूहे को जहर देना है।

मोदी सरकार मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की साजिश में जुटी - नाना पटोले

मुंबई : मोदी सरकार ने आगामी १८ से २२ सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। केंद्र सरकार की ओर से इस विशेष सत्र का एजेंडा नहीं बताया गया है। मोदी सरकार ने विपक्ष, संसदीय कार्य समिति समेत किसी से पूछे बिना यह सत्र बुलाया है। यह विशेष सत्र देश को बांटने के लिए बुलाया गया है। मोदी सरकार मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की साजिश में जुटी है। यह गंभीर आरोप महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने लगाया है।

सोमवार को मीडिया से बोलते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। इसके अलावा नोटबंदी के पैष्ठसले और मणिपुर में जारी हिंसा के मुद्दे पर भी कभी विशेष सत्र नहीं बुलाया गया, लेकिन अब अपनी मनमर्जी और मनमानी के तहत विशेष सत्र बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि मुंबई अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शहर है, देश की आर्थिक राजधानी है। यह शहर महाराष्ट्र के साथझसाथ देश का गौरव है। भाजपा और मोदी सरकार की साजिश के तहत मुंबई के सभी सत्ता केंद्रों को गुजरात ले जाने की है। पिछले ९ सालों में मुंबई के महत्व को कम करने का काम कई बार किया गया है। इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर को गुजरात में स्थानांतरित करने के बाद, मुंबई में बड़ा हीरा बाजार को भी गुजरात शिफ्ट कर दिया गया है। मुंबई से एयर इंडिया का मुख्यालय शहर से बाहर चला गया। अब बीएसई और एनएसई को गुजरात ले जाने की योजना है। पटोले ने कहा कि मोदी सरकार मुंबई को तोड़ने की साजिश रच रही है।

सीएम, दोनों डीसीएम को चुनौती

पटोले ने कहा कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने में महाविकास आघाड़ी सरकार बाधक थी, इसलिए केंद्र सरकार और राज्यपाल की मदद से माविआ सरकार को उखाड़ फेंका गया। अब जब से राज्य में असंवैधानिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार आई है, मुंबई और महाराष्ट्र की बड़ी परियोजनाओं पर गुजरातियों ने कब्जा कर लिया है। लेकिन डीसीएम देवेंद्र फडणवीस में इस पर विरोध करने की हिम्मत नहीं है। नाना पटोले ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर शिंदे-फडणवीस और अजीत पवार में हिम्मत है, तो वे महत्वपूर्ण कार्यालयों और परियोजनाओं को मुंबई से बाहर ले जाने के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उनसे सवाल करके दिखाएं।

मुंबई/ रिक्शे में 12 दिन के नवजात को छोड़कर भागी मा

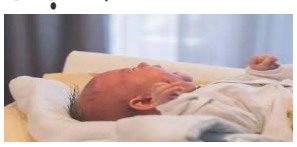

मुंबई : जोन 7 के अधीन के कांजुरमार्ग पुलिस की हद में खड़े एक रिक्शे की पिछली सीट पर 10-12 दिन का बच्चा पाया गया है।पुलिस इस मामले में मामला दर्ज कर उस कुमाता बनी माता की तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार कांजुरमार्ग पूर्व स्थित वात्सल्य ट्रस्ट के गेट के सामने खड़े रिक्शा क्रमांक एम. एच.03.बी. एन.2966 के पिछली सीट पर एक कपड़े में लपेटे हुए बच्चा होने की जानकारी पुलिस को मिली।इस सुचना को प्राप्त कर मौके पर पहुंची पुलिस ने उस लड़का जाति के नवजात मतलब 10 या 12 दिवसीय बच्चे को अपने कब्ज में लिया।वरिष्ट पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर पीएसआई शेख ने यह मामला अपराध क्रमांक 95/2023 भादवी 317 सह 75 अल्पवयिन न्याय अधिनियम 2015 के तहत मामला दर्ज किया है।मामले की अधिक जांच व उस माता से कुमाता बनी माता की तलाश कर रहे हैं।

54 विधायकों की 'अयोग्यता' पर 14 सितंबर को महाराष्ट्र विधानसभा में सुनवाई,

शिंदे बनाम उद्धव में किसकी होगी जीत ?

मुंबईः एकनाथ शिंदे सेना और उद्धव ठाकरे सेना के विधायकों की पात्रता और अपात्रता मामले में जल्द ही फैसला हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर 14 सितंबर से इस मामले की सुनवाई करेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए अध्यक्ष नार्वेकर ने कहा कि कार्यवाही संवैधानिक तरीके से की जाएगी। सभी को अपनी बात रखने का पूरा वक्त दिया जाएगा। किसी के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। महाराष्ट्र विधान भवन के सेंट्रल हॉल में 14 अगस्त की दोपहर 12 बजे से विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की उपस्थिति में सुनवाई शुरू होगी।

यह मामला शिंदे सेना के 40 और उद्धव सेना के 14 विधायकों की पात्रता और अपात्रता से संबंधित है। महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय ने सुनवाई के लिए 8 जुलाई को ही सभी 54 विधायकों को नोटिस भेजा है। सुनवाई के लिए दोनों गुटों के विधायकों को प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहना होगा। विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष 34 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान वादी और प्रतिवादी विधायकों को सबूत पेश करने और अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। प्रत्येक याचिका पर अलग से सुनवाई होगी और संबंधित विधायकों को उस समय बुलाया जाएगा। गणेशोत्सव से पहले महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार, NCP विधायकों को मौका... जानें अजित पवार के खास का दावा

क्या है मामला

शिवसेना में विभाजन के बाद 56 विधायकों में से 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ और शेष 16 विधायक उद्धव ठाकरे के साथ चले गए। इसी तरह से लोकसभा में शिवसेना के चुनाव चिन्ह 'धनुष बाण' पर निर्वाचित होनेवाले 18 सांसदों में से 13 सांसद शिंदे गुट में शामिल हो गए, जबकि पांच सांसदों ने उद्धव के साथ रहने का फैसला किया।

सरकार का भविष्य तय करेगा यह फैसला

विधानसभा अध्यक्ष की सुनवाई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित कई विधायकों की किस्मत का फैसला होगा। साथ ही सरकार का भविष्य भी तय होगा। शिंदे गुट के साथ ही ठाकरे गुट की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। सुनवाई के बाद ही तय होगा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी रहेगी या नहीं। विधायकों की पात्रता और अपात्रता का फैसला होने के बाद चुनाव आयोग के नतीजे भी बदलने की संभावना जताई जा रही है। उद्धव सेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को सुनवाई पूरी कर फैसला दे देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि विधानमंडल के सभी नियमों को परे रखकर उन्होंने इतना विलंब कर दिया।

EC-SC ने दी थी शिंदे गुट को राहत...

बता दें कि इसी साल 17 फरवरी को चुनाव आयोग ने शिंदे-गुट को असली शिवसेना के रूप में वैध ठहराया और उसे धनुष और तीर का प्रतीक आवंटित किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी 11 मई को कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में ठाकरे की स्थिति बहाल नहीं की जा सकती क्योंकि उन्होंने फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दे दिया था। कोर्ट ने तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के कामकाज पर उंगली उठाई थी। कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष से विधायकों की पात्रता और अपात्रता पर निर्णय लेने के लिए कहा था।

महाराष्ट्र के सतारा में हुई हिंसक झड़प के बाद इलाके में धारा 144 लागू

इंटरनेट बंद, एक की मौत और 10 घायल

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के सातारा जिले के पुसेसावली गांव में सोशल मीडिया पर महापुरुषों को लेकर किए एक विवादित पोस्ट के बाद दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई. दोनों समुदायों के बीच हुए साम्प्रदायिक हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई. 10 लोग घायल हो गए. पुलिस ने इस मामले में अबतक 23 लोगों को गिरफ्तार किया है. हिंसा के बाद एहतियात के तौर पर पूरे जिले में इंटरनेट बंद कर दिया गया है. इलाके में धारा 144 लगा दिया गया है. गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. स्थानीय पुलिस के साथ-साथ रफ्तक्रकी टुकड़ी भी डिप्लॉय की गई है. फिलहाल पुलिस का दावा है कि स्तिथि इस समय नियंत्रण में है.

कब और कैसे भड़की हिंसा?

दरअसल रविवार की रात करीब 9 से 10 बजे के बीच एक समुदाय के लोग जब अपने धर्मस्थल में प्राथना करने के लिए पहुंचे हुए थे... कुछ देर बाद उसी जगह पर

दूसरे समुदाय के लोग पहुंचते हैं. दोनों के बीच सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कहासुनी शुरू होती है. बात आगे बढ़ते-बढ़ते पथराव और आगजनी तक पहुंच जाती है. कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और दुकानों में तोड़फोड़ की गई. उसके बाद प्रशासन कि और से जिले में इंटरनेट सेवा बंद करने का ऐलान किया गया. और पुलिस की और से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है. महाराष्ट्र के सतारा में हुई हिंसा के सिलसिले में अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. एहतियात के तौर पर जिले में इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है.

दैनिक रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : बुधवार 13 सितंबर 2023

मनसे ने दी एमएमआरडीए प्रशासन को फ्री वे ब्रिज के बोर्ड को लेकर चेतावनी

माऊली थोरवे ने अंग्रेजी में लिखा फ्रीवे पर सीएसटी ब्रिज बोर्ड हटाये प्रशासन अन्यथा तोड़े देंगे ।

मुंबई (फिरोज सिद्दीकी) अभी आगामी मुंबई महापालिका चुनावों तो कहने को काफी दूर है परंतु अभी से ही विभिन्न राजनीतिक पार्टियां मौजुदा समय में कोई न को मुद्दा उछालकर चर्चा सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ मामला चेंबूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में देखने को मिला है । बताते है की मनसे प्रदेश वाहातुक सेना महासचिव व चेंबूर विधानसभा अध्यक्ष माऊली थोरवे ने एमएम आरडीए प्रशासन को 15 दिनो का अल्टीमेटम देते हुए कहा की हमारे आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर मराठी भाषा में बदले । चेंबूर से लेकर मुंबई फ्री वे एक्सप्रेस हाई वे के अंग्रेजी के लिखे बोर्ड नही बदलेंगे तो तोड़ दिए जायेंगे । सूत्रों के अनुसार प्रशासनिक विभाग के अधिकारियो के हाथ पैर पहले से ही फूल गये है मनसे की चेतावनी को लेकर , सांस्त में पड़ गाये संबंधित विभाग के अधिकारीगण ।

गणेश मूर्ति पर मोहर लगाने को लेकर पालकमंत्री लोढ़ा ने जताई आपत्ति, कमिश्नर को लिखा पत्र...

मुंबई : गणेशोत्सव शुरू होने के लिए अब बस कुछ दिन ही बचे है। नगर पालिका की ओर से मूर्ति विक्रेताओं को गणेशोत्सव में POP और इको-फ्रेंडली मूर्तियों की पहचान करने के विशेष निर्देश दिए गए। जी हां आपको आपको बता दें कि इन निदेर्शों के मुताबिक इको-फ्रेंडली मूर्ति के कंधे पर हरा निशान और पीओपी POP मूर्ति के कंधे पर लाल निशान करना था। नगर निगम अधिकारियों को उम्मीद थी कि इससे ग्राहकों के लिए मिट्टी और पीओपी की मूर्तियों की पहचान करना संभव हो सकेगा। ऐसे में अब इस विषय को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि, मूर्ति पर इस तरह की मोहर लगाने से श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं, इसलिए नगर पालिका को इसका कोई दूसरा विकल्प तलाशना चाहिए। पर्यावरण के अनुकूल गणेश मूर्तियों को बढ़ावा देने के लिए, नगर निगम आयुक्त ने अधिकारियों को शाडू मिट्टी से भगवान गणेश की मूर्तियां बनाने के लिए मूर्तिकारों को नगर निगम के प्रत्येक विभाग में एक स्थान मुफ्त प्रदान करने का निर्देश दिया।

लाखों हिंदुओं के लिए चिंता का विषय

इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ ही प्रायोगिक स्तर पर कुछ मात्रा में शाडू मिट्टी भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। इस बीच, जनजागरूकता पैदा करने के लिए, नगर पालिका ने मूर्तिकारों को अंतर समझने के लिए इको-फ्रेंडली मूर्ति के दाहिने कंधे के पीछे एक छोटा हरा चिन्ह और पीओपी मूर्ति के पीछे एक छोटा लाल चिन्ह बनाने का निर्देश दिया था, हालांकि इस विषय पर पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने कमिश्नर को पत्र लिखकर मांग की है कि गणेशोत्सव लाखों हिंदुओं के लिए चिंता का विषय है और इस फैसले के बजाय कोई अन्य विकल्प खोजा जाना चाहिए।

कमिश्नर चहल से लोढ़ा की चर्चा

इस विषय को लेकर पालकमंत्री लोढ़ा और कमिश्नर की आपस में चर्चा हुई है। मुंबई में गणेशोत्सव का विशेष महत्व है और हर व्यक्ति गणेश जी की मूर्ति को पवित्र मानकर उनकी पूजा करता है। अतः इस पृष्ठभूमि में उन्होंने यह राय व्यक्त की कि मूर्ति पर मोहर लगाना या रंग-रोगन करना उचित नहीं है। ऐसे में अब लोढ़ा ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों और अन्य मूर्तियों के बीच अंतर को समझने के लिए उन्होंने नगर निगम आयुक्त इकबाल सिंह चहल से मूर्ति पर पेंटिंग या मोहर लगाने के बजाय दूसरा विकल्प ढूंढने के बारे में बात की है।

मनपा के खजाने में 28 करोड़ एक लाख 89 हजार 698 रुपए जमा

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली मनपा क्षेत्र में लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जिसके माध्यम से मनपा के खजाने में 28 करोड़ एक लाख 89 हजार 698 रुपए जमा हुआ। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर लोक अदालत का आयोजन किया गया था। केडीएमसी क्षेत्र में 27 हजार 973 संपत्ति कर बकाएदारों को नोटिस दी गई थी। 1,018 बकाएदारों ने कुल 28 करोड़ एक लाख 89 हजार 698 रुपए मनपा में संपत्ति कर के रूप में जमा किए। मनपा ने स्पष्ट किया है कि अभय योजना की अवधि को भी 15 सितंबर तक बढ़ाया गया है। अतः नागरिक इसका लाभ लें।

अवैध बैनर व होर्डिंग से पटा भिवंडी शहर

मनपा के राजस्व को लग रहा बड़ा नुकसान...

अवैध होर्डिंगों की वजह से समूचा शहर गंदा... कार्यवाई को लेकर मनपा प्रशासन बनी उदासीन

मुस्तकीम खान

भिवंडी : भिवंडी शहर में मनपा प्रशासन की उदासीनता से अवैध बैनर,पोस्टर की बाढ़ सी आ गई है।जिसके कारण मनपा के राजस्व को भी काफी नुकसान हो रहा है।इतना ही नही इन अवैध होर्डिंगों की वजह से समूचा शहर गंदा हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मनपा द्वारा कार्रवाई न किए जाने से अवैध पोस्टर लगाने वालों के हौसले बुलंदी पर हैं। गौरतलब है कि भिवंडी शहर में इन दिनों दीवारों, फ्लाईओवर के पिल्लरों, इलेक्ट्रिक खंभों सहित तमाम सार्वजनिक स्थलों पर राजनीतिक दलों द्वारा बगैर मंजूरी के लगाए गए अवैध बैनर, पोस्टर से समूचा शहर पटा पड़ा है। परवाना विभाग की लापरवाही की वजह से इस कारण प्रतिवर्ष मनपा को करोड़ों का नुकसान हो रहा है।लोगों का आरोप है पैसा लेकर बिना परमिशन अवैध बैनर,पोस्टर लगाकर शहर की खूबसूरती खराब

करने वाले काफी लोग शहर भर में सक्रिय है।जो मनपा परवाना विभाग के अधिकारियों को कुछ ले-देकर मनचाही जगहों पर बैनर,पोस्टर लगा रहे हैं।शहर के मानसरोवर ,धामनकर नाका, कल्याण नाका,बंजारपट्टी सहित शहर का हर गली मोहल्ले अवैध बैनर पोस्टरों से पट गया है।जिसकी शिकायत के बाद भी रिश्वतखोर मनपाकर्मी बैनर, पोस्टर को हटाने के लिए बहानेबाजी करते दिखाई पड़ते हैं।आलम यह है कि कार्यक्रमों के समाप्ति के हप्तों बाद भी अवैध बैनर पोस्टर नही हटाए जा रहे है।जिसके कारण मनपा को हर वर्ष न सिर्फ करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है।बल्कि शहर की सुंदरता भी खराब हो रही है।साथ ही अवैध बैनर, पोस्टर को लेकर हाईकोर्ट के जारी दिशा-निदेर्शों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन हो रहा है।जिसके खिलाफ स्थानीय नागरिक हाईकोर्ट के निदेर्शों का हवाला देते हुए कोर्ट जाने की तैयारी में है। नागरिकों का कहना है कि यदि मनपा अवैध बैनर, पोस्टरों के लगाने वालों पर कार्रवाई नहीं करती तो मनपा प्रशासन के खिलाफ भी कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी । मनपा प्रवाना विभाग प्रमुख प्रकाश राठोर से इस संबंध में बात करने की कोसिश की गई परन्तु उन्होने फोन नहीं उठाया,अवैध बैनर, पोस्टर को हटाने के लिए मनपा द्वारा परवाना विभाग बनाया गया है जहां पर लोग अनुमति लेकर बैनर पोस्टर लगाएं,लेकिन विभाग के भ्रष्ट कार्य की वजह से अवैध बैनर,पोस्टर लगाने वालों पर कार्यवाई नहीं हो रही है। इस कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी, कर्मचारीयों पर कब कार्यवाई होगी।

रिक्शे की टक्कर से एक की मौत,केस दर्ज कर रिक्शा चालक की तलाश में जुटी पुलिस

मुस्तकीम खान

भिवंडी : रिक्शे द्वारा बाइक को पीछे से टक्कर मारने के कारण बाइक चालक की मौत हो गई।उक्त दुर्घटना आगरा रोड पर स्थित सिटीजन हॉस्पिटल के सामने की है।पुलिस ने फरार अज्ञात रिक्शा चालक पर केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दिया है। पुलिस के अनुसार भिवंडी निवासी संतोष गोपाल केजरीवाल(55) सोमवार की सुबह 10.30 बजे टीवीएस एम एच 04 एच आर 2283 द्वारा काम पर जा रहा था।जैसे ही वह आगरा रोड द्वारा कमला

होटल के आगे सिटीजन हॉस्पिटल के सामने पहुंचा,पीछे से तेजगति से आ रही रिक्शे ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।जिसके कारण बाइक सवार गिर गया।इस कारण उसके सिर में गंभीर चोट लगने के कारण लहूलुहान हो गया।इधर दुर्घटना के बाद रिक्शा चालक मानवता को ताक पर रखकर घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के बजाय फरार हो गया।दुर्घटना के बाद घायल संतोष को उसके मित्र ने इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में लेकर गया।जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।मृतक व्यक्ति के मित्र की शिकायत पर भिवंडी शहर पुलिस ने अज्ञात रिक्शा चालक पर 304 (अ) व 279,134 (अ) (ब)के तहत केस दर्ज कर फरार रिक्शा चालक की तलाश शुरू कर दिया है।

एटीएम मशीन में चोरी का प्रयास करते दो गिरफ्तार

मुस्तकीम खान

भिवंडी : भिवंडी के कोनगांव पुलिस ने दो युवकों को एटीएम मशीन में छेड़छाड़ करने और चोरी का प्रयास करने के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार रविवार की रात पौने दस बजे कोनगांव स्थित अस्मिता गेट के पास लगे हिताची एटीएम का दरवाजा खुला देख अंबरनाथ निवासी करमजीत बाबूलाल पासवान 23 वर्ष

और उदयराज रामस्वरूप गौतम 32 वर्ष यह दोनों युवक हिताची एटीएम में प्रवेश किए और मशीन में लोखंड की पट्टी डाल कर चोरी करने का प्रयास किया। जिन्हें कोनगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने आईपीसी की धारा 380, 511, 427 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की कार्रवाई सहायक पुलिस निरीक्षक कडलग कर रहे है।

मालिक , मुद्रक,प्रकाशक ,संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिंटिंग प्रेस , गाला नं 3 - 4 ,अमीन इंडस्ट्रियल इस्टेट ,सोनावला क्रॉस रोड नं 12 ,गोरगांव (पूर्व),मुंबई 63 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : 1 -ए, ग्राउंड फ्लोर साहिल मेंशन, बालमिया लेन, माहिम वेस्ट मुंबई 400016 मोबाइल नं 9987 77 5650 व्हाट्सप्प नं 7977 40 8589 : Email - editor@rokthoklekhaninews.com